ए-45011/4/2023-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को जुलाई, 2023 माह में आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के मासिक सारांश के अगोपनीय भाग को परिचालित करने का निदेश दिया गया है।

सु. सामंत
(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 2309- 5244

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (एफ) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, एएस एंड एफए (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी/सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, एएस (जी-20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागों के प्रमुख।

संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (निवेश)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (एफएम)/सभी सलाहकार/सीएएए

17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फ़ाइल - 2023.

ए-45011/4/2023-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषय: जुलाई, 2023 के महीने में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का मासिक सारांश।

1. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृहत आर्थिक अवलोकन:

घरेलू निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष *2023* की चौथी तिमाही में उम्मीद से अधिक वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष *(आईएमएफ)* ने जुलाई *2023* के विश्व आर्थिक परिदृश्य *(डब्ल्यूईओ)* में वित्त वर्ष *2024* के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को *20* आधार अंकों तक संशोधित किया है। सरकार के पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने के परिणामस्वरूप घरेलू निवेश में वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित उपायों ने राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में राज्यों के पूंजीगत व्यय में वार्षिक आधार पर 74.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और इसी तिमाही में केंद्र के पूंजीगत व्यय में भी 59.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जुलाई 2023 में हेडलाइन सीपीआई-सी मुद्रास्फीति बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई और यह मुख्य रूप से विशिष्ट खाद्य वस्तुओं मूल्य में वृद्धि के कारण हुई, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति 39 महीने के निचले स्तर पर रही। 48 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक है और इसमें 14 खाद्य वस्तुएं शामिल हैं जिनकी मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में है। इसलिए, कुछ विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण जुलाई 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति की दर ऊँची रही जो आने वाले महीनों में कम होने की संभावना है।

खुदरा मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि के कारण, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया है कि मुद्रास्फीति विकास में सहायक बनी रहे और लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखित हो। इस संदर्भ में, एमपीसी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 5.1 प्रतिशत से संशोधित कर 5.4 प्रतिशत कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 2024

की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति क्रमशः 6.2 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, और इनमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

बाजार में ताजा आवक के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के नियमित बेहतर प्रदर्शन से आपूर्ति में व्यवधान और उच्च अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने में मदद मिलेगी। ई1 नीनो के डर के बावजूद, मानसून की प्रगति अब तक काफी सक्रिय रही है, हालांकि क्षेत्र-वार असमानता रही। देश के लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य या अधिक बारिश हुई है। 18 अगस्त 2023 तक, किसानों ने 102.3 मिलियन हेक्टेयर में बुवाई की है, जो पिछले साल की इसी अवधि के स्तर के समान है और पिछले पांच वर्षों के औसत से 1.1 प्रतिशत अधिक है।

धीमें वैश्विक विकास परिदृश्य के बीच, भारत के निर्यात ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024 से 23 जुलाई तक) के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य कारण सेवा निर्यात में वृद्धि है, जो महामारी के बाद उत्थानपरक सेवाओं की मांग के वैश्विक रुझान के अनुरूप है। सेवा व्यापार अधिशेष में परिणामी वृद्धि ने इस अवधि के दौरान समग्र व्यापार संतुलन में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुलाई 2023 में, सेवा निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो जुलाई 2022 की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2023 में सेवा व्यापार अधिशेष में सालाना आधार पर 20.8 प्रतिशत का सुधार हुआ। इसी महीने के दौरान, भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट आई।

नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट भारत में बहुआयामी गरीबी की व्यापकता में उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डालती है। राष्ट्रीय एमपीआई 2015-16 में 0.117 से घटकर 2019-21 में लगभग आधा अर्थात 0.066 हो गया है, जिससे भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने का) को प्राप्त करने के रास्ते पर है, जो वर्ष 2030 की निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले है। नतीजतन, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों का बहुआयामी गरीबी से निजात का अनुमान है।

2. **महत्वपूर्ण घटनाक्रम:**

(i) इस महीने के दौरान जी-20 में भारत की अध्यक्षता के तहत **निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें** आयोजित की गईं:

(क) जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की तीसरी बैठक **17-18 जुलाई 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई।** बैठक की अध्यक्षता भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संयुक्त रूप से की।

(ख) एफएमसीबीजी की बैठक से पहले जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक की तीसरी बैठक हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने जी-20 परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष की ओर से जारी सारांश (ओडीसीएस) पर बातचीत की, जिसे बाद में मंत्रियों और गवर्नरों द्वारा अंगीकार किया गया।

(ग) नई दिल्ली में 9-10 सितंबर, 2023 को आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में तीसरी जी-20 एफएमसीबीजी बैठक के दौरान हुई चर्चा शामिल होगी। जुलाई ओडीसीएस वित्त ट्रैक से संबंधित पैराग्राफ तैयार करने का आधार बनेगा जिसे जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में शामिल किया जाएगा।

(घ) जी-20 एफएमसीबीजी और जी-20 एफसीबीडी बैठकों की तर्ज पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

i. 2023 जी-20 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग - भावी शहरों के लिए वित्त पोषण और वित्तपोषण तंत्र और दृष्टिकोण का लाभ उठाना।

ii. कर चोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन से निपटने के लिए जी-20 उच्च स्तरीय कर संगोष् ठी।

iii. नीति संवाद: क्रिप्टो आस्तियों पर गोलमेज चर्चा।

iv. एमडीबी को सुदृढ़ करने पर जी-20 विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर जी-20 गोलमेज सम्मेलन।

v. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के अनुकूल जलवायु कार्रवाई और वित्तपोषण प्राप्त करना।

(ङ) माननीय वित्त मंत्री ने गांधीनगर में चुनिंदा जी-20 और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (आईओ) के अपने समकक्षों अर्थात् कनाडा, बांग्लादेश, नेपाल, ईसी, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया और एआईआईबी के साथ आठ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं।

(च) माननीय वित्त मंत्री ने 19 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष से भी मुलाकात की।

(ii) इस माह के दौरान **निम्नलिखित** अधिसूचनाएं जारी की गईं:

(क) **दिनांक 26 जुलाई, 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कॉरपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना (जीएससीडी)** - बाजार में स्थिरता लाने की दृष्टि से बाजार अव्यवस्था के समय कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि, प्रासंगिक सेबी विनियमों के तहत बनाया

गया/बनाया जाने वाला एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले ऋण के खिलाफ 100% गारंटी कवर प्रदान करना।

(ख) **भारत की जी-20 अध्यक्षता के अवसर पर** ₹100/- और ₹75/- के स्मारक सिक्के।

(iii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित **महत्वपूर्ण बैठकें** आयोजित की गईं/उनमें भाग लिया गया:

(क) एआईआईबी सहायता प्राप्त 30 परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 28 जुलाई, 2023 को त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक (टीपीआरएम) आयोजित की गई थी।

(ख) वित्तीय स्थिरता परिदृश्य, क्रिप्टो-आस्तियों, जलवायु रोडमैप और टीसीएफडी के भविष्य आदि पर चर्चा करने के लिए एफएसबी की पूर्ण बैठक 06 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई थी।

(ग) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 31 जुलाई, 2023 को आ.का.वि. स्क्रीनिंग समिति की 141वीं बैठक आयोजित की गई।

(घ) 04 जुलाई, 2023 को दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड के माध्यम से ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की तीसरी बैठक।

(ङ) 12 जुलाई, 2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ता का 15 वां दौर।

(iv) **भारत ने 24 जुलाई, 2023 के फैसले के तहत गुणावगुण के आधार पर भारत मॉरीशस बीआईटी के तहत लाए गए जीपीआईएक्स बनाम भारत गणराज्य विवाद को जीत लिया है।**

(v) भारत ने 12 जुलाई, 2023 को कार्यकारी बोर्ड की बैठक के माध्यम से आईएमएफ में पाकिस्तान के एसबीए अनुरोध से दूर रहने के अपने रुख से अवगत कराया।

(vi) 03 जुलाई, 2023 को एसजीएक्स निफ्टी डेरिवेटिव्स का एनएसई आईएफएससी में परिवर्तन हुआ।

(vii) **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए/ बातचीत की गई:**

क) मध्य प्रदेश सरकार की "इंदौर मेट्रो लाइन 3 परियोजना" के वित्तपोषण के लिए 225 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए 10 जुलाई, 2023 को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ समझौता।

ख) मेघालय में ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने और प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुभवात्मक पारिस्थितिकी-पर्यटन विकास के वित्तपोषण के लिए 79.05 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए एनडीबी के साथ करार।

ग) पैकेज 3, कॉरिडोर 4 चरण-II के लिए चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए 347 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए एनडीबी के साथ समझौता।

घ) चयनित शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और शहरी समुत्थानशीलता और विरासत को बढ़ाने के लिए चल रही राजस्थान माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ङ) बिहार सड़क परियोजना में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाने के लिए 295 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए एडीबी के साथ करार।

(viii) इस महीने के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) आईआईबीएफ मुंबई में 'परियोजना वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

(ख) आईआईएम कोझिकोड में 'बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

(ग) आईआईएम शिलोंग में 'समकालीन परियोजना प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

(घ) आईआईएम लखनऊ में 'परियोजना प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

(ङ) आईआईएम रायपुर में 'परियोजना व्यवहार्यता और परियोजना वित्तपोषण और निष्पादन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

3. **न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन**

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. **एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना:** शून्य

5. **विभाग में माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:**

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	03
विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षाधीन	:	08